



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ 1931 (श0)  
(सं0 पटना 64) पटना, सोमवार, 25 जनवरी 2010

सं. 2/स्था.-5-01/10-460

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

19 जनवरी 2010

विषय:—बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के अधीन नियमित नियुक्ति होने तक रिक्तियों को भरने हेतु अंतरिम व्यवस्था।

ग्रामीण विकास विभाग में गरीबी उन्मूलन के तहत नये कार्यक्रमों के सृजन एवं उनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के आलोक में पदाधिकारियों का सम्बर्ग विकसित करने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना सं. 447 दिनांक 19 जनवरी 2010 द्वारा बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग का गठन किया गया है। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग में यह प्रावधानित है कि बेसिक ग्रेड में ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की जानी है तथा कम से कम 3 (तीन) वर्षों की सेवा के उपरान्त ही उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली 2010 के नियम 8 (ख) में यह प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए अंतरिम व्यवस्था की जा सकेगी।

राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त प्रखंड विकास पदाधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए निम्न प्रकार अंतरिम व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया है :-

(1) प्रखंड विकास पदाधिकारियों के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु पदाधिकारियों के लिए निम्न अहर्ता रहेगी—

- (1) संबंधित पदाधिकारी कम से कम स्नातक या समकक्ष योग्यताधारी हों।
- (2) संबंधित पदाधिकारी कम से कम अपुनरीक्षित वेतनमान 5000-8000 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 (पी0बी0-2) ग्रेड वेतन ₹0 4200 होगा, में कार्यरत हों।
- (3) सरकारी सेवा में पदाधिकारी को कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो।
- (4) पदाधिकारी की उम्र अधिकतम 52 वर्ष होनी चाहिए।

(2) यह प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति अधिकतम 3 वर्षों के लिए ही होगी। नियमित नियुक्ति होने पर यह प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी। प्रतिनियुक्ति पर कार्यावधि की समाप्ति के उपरान्त ऐसे पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। चयनित पदाधिकारी अपने वेतनमान में ही कार्य करेंगे। नियमानुसार उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।

(3) पदाधिकारियों के विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन संबंधित विभाग के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा।

(4)(क) प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु पैनल निर्धारण करने के लिए एक चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जाएगी :-

(क) विकास आयुक्त	-	अध्यक्ष
(ख) प्रधान सचिव / सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	-	सदस्य
(ग) कार्मिक विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी	-	सदस्य
(घ) प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य सचिव

(ख) समिति पैनल निर्धारण करने के लिए आवश्यक मापदंड एवं प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकेगी।

(ग) निर्धारित रिक्तियों के दो गुणा पदाधिकारियों का पैनल निर्धारण किया जाएगा।

(घ) पैनल से पदस्थापन क्रमवार किया जाएगा।

(6) सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किसी भी समय पदाधिकारी की सेवाएँ वापस की जा सकेगी।

(7) यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 64-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>